LOK SABHA

Thursday, May 15, 1969/Vaisakha 25, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

1. SHRI V. K. KRISHNA MENON— (Midnapore)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में गौ-हत्या तथा गोमांस के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

+

*1711. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदानन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् ने अपने द्वारा एक पारित संकल्प भेजा है जिसमें दिल्ली भर में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है ;

(ख) संकल्प किस तारीख को भेजा गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार दिल्ली में गो-मांस के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (d). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d). Yes, Sir. The Delhi Administration forwarded to the Government of India on the 16th December, 1967 the Delhi Cow Protection Bill, 1967 passed by the Metroplitan Council in its Sitting held on 14th November, 1967. This Bill sought to prohibit in the Union Territory of Delhi, the slaughter of cow, including bulls and bullocks of any age, even after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals. While forwarding the draft Bill, the Delhi Administration referred to the judgement of the Supreme Court in the case of Mohammed Haneef Quereshi and others *vs.* State of Bihar (1959) and recommended that the Constitution should be amended to provide for total ban on cow slaughter. The proposed restriction would be unconstitutional. Total prohibition on the use of "beef" as defined in the Delhi Cow Protection Bill, amounting to imposition of undue restrictions would be *ultra vires* of Article 19 (1)(g) of the Constitution. It was decided by Central Govt. that the recommendation of Delhi Administration should be considered after receipt of the report of the Committee on Cow Protection, which was examining the question of cow protection in all its aspects.

श्री श्रीगोपाल साबू : अध्यक्ष महोदय, यह सभापटल पर जो आप ने रखा उस में यह कहा गया है कि दिल्ली प्रशासन की इस सिफारिश पर गोरक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गोरक्षा समिति के अनेक व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिया है, उस का काम अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है तो क्या उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा न करके दिल्ली प्रशासन की सिफारिशों को तुरन्त स्वीकार कर